नईदुनिया

मंदिरों में चढ़ावे की चोरी : भक्तों की आस्था पर प्रहार

डॉ. विश्वास तिवारी

अयोध्या में चढ़ावे की चोरी का मामला अभी गर्म ही था, तभी बद्रीनाथ मंदिर में भी दान राशि की हेराफेरी का मामला उजागर हो गया। इसके अलावा वाराणसी के बांके बिहारी और नलखेड़ा में स्थित देवी के मंदिरों में भी चढ़ावे की राशि से छेड़छाड़ का मामला भी चर्चा में आ गया। हिंदू संस्कृति में मंदिरों में दान की परंपरा बहुत पुरानी है। देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु जिसमें से अधिकांश अपना एक एक पैसा बचाकर, पेट काटकर, पैसे जोड़कर तिरूपति बालाजी, बद्रीनाथ और सोमनाथ जैसे कई मंदिरों में अपनी पूंजी अर्पित करते है ये चढ़ावा वो अपने बच्चों के लिए, परिवार में किसी की सेहत के लिए या अपने व्यवसाय या किसानी के लिए भगवान से मन्नत मांगते है। श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट के महासचिव चपंत राय बंसल और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया और देरी से ही सही उसे स्वीकार भी कर लिया गया। उत्तरप्रदेश सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एसआईटी का गठन किया और प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इस कार्रवाई के बाद आठ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और उनसे नगदी और गहनों की बरामदगी भी की गई। जांच में पता चला है कि इन पैसों से इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदी थी, शेयर बाजार और ब्याज पर पैसा चलाया था।

इस पूरे मामले में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दान में मिले रुपयों की गिनती आएसएस और बीएचपी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही होती थी। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन से आएसएस और उससे जुड़ें संगठन मुख्यधारा में आ गए थे, लेकिन चढ़ावे में चोरी की बात सामने आने पर इन संगठनों की ईमानदारी पर भी सवाल उठ रहे है।

मर्यादा पुरूषोत्तम राम में हर सनातनी की गहरी आस्था है और वह सदैव रहेगी भी लेकिन उनसे जुड़े किसी भी कार्य में किसी भी अमर्यादित आचरण से लोगों में क्रोध उभरना स्वाभाविक है। पहले मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा, ध्वस्त किया, वहां मस्जिदें और मजार बनवाई और फिर अंग्रेजों ने हमारे मंदिरों की संपत्ति को हड़पा और अब हम स्वयं ही अपने अपने मंदिरों में यह कार्य करेंगे तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। मुगल और अंग्रेज तो दूसरे देशों से आए थे, लेकिन यहां तो हमारे देश के

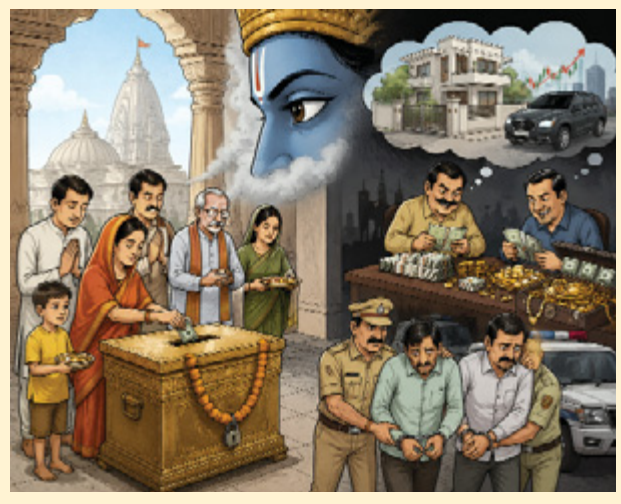

मर्यादा पुरूषोत्तम राम में हर सनातनी की गहरी आस्था है और वह सदैव रहेगी भी लेकिन उनसे जुड़े किसी भी कार्य में किसी भी अमर्यादित आचरण से लोगों में क्रोध उभरना स्वाभाविक है। पहले मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा, ध्वस्त किया, वहां मस्जिदें और मजार बनवाई और फिर अंग्रेजों ने हमारे मंदिरों की संपत्ति को हड़पा और अब हम स्वयं ही अपने अपने मंदिरों में यह कार्य करेंगे तो यह हमारे लिए शर्म की बात है।

लोग ही भगवान के घर में चोरी कर रहे है और यह वो ही लोग है जिन्हें राम मंदिर जैसे पवित्र जगह सेवा करने का अवसर मिला है। वह किसी अन्य धर्म या संस्कृति से नहीं है, बल्कि वे स्वयं को सनातनी कहने वाले, माथे पर तिलक लगाने वाले मंत्रों का जाप करने वाले लोग है जिन्हें पावन संपत्तियों की रखवाली का जिम्मा सौंपा था। यहां तो वही स्थिति हो गई कि चोर को ही खजाने की चाबी थमा दी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि रामलला को सौंपने का फैसला सुनाया था, उसी फैसले में सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि वह मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक न्यास (ट्रस्ट) का गठन भी करें।

पहले राम मंदिर के निर्माण में राजनीति हुई, फिर ट्रस्ट के गठन और उनके सदस्यों के नामों को लेकर भी असहमति हुई और तो और मंदिर निर्माण के बाद उसके लोकार्पण की तिथि और समारोह से शंकराचार्यों की दूरी ने भी विवाद खड़ा कर दिया। एसआईटी अपनी जांच तेज गति से कर रही है और अब कोर्ट को भी फॉस्टट्रैक करके अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए ताकि लोगों के मन में यह भ्रम न रहे कि जो हमने प्रभु राम को अर्पण किया है वो कही चोरी न हो जाए। उचित कार्रवाई के साथ-साथ ट्रस्ट में भी एक संपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न हो सके। हर वर्ष वहां के चढ़ावे और खर्चे का योग्य व्यक्तियों द्वारा ऑडिट कराया जाना चाहिए। जब अयोध्या में इतना दान आ रहा है तो इसका उपयोग जनहितेशी कार्यों में किया जाना चाहिए। वहां गरीबों के लिए 24 घंटे रसोई खोली जा सकती है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल खोले जा सकते है। भगवान राम को पैसे कि क्या जरूरत है? यह भी सही है कि इतने बड़े परिसर की सुरक्षा और देखरेख के लिए काफी खर्चा होता होगा, लेकिन ऐसे दान का उपयोग जनता के लिए होगा तो लोगों का ऐसे ट्रस्ट मे विश्वास बहाल होगा। चढ़ावे वाली जगह से लेकर गिनती वाली जगह तक अगर सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जाती तो यह गड़बड़ियां पहले ही पकड़ में आ सकती थी।

एक सवाल और उठता है कि इस ट्रस्ट को सूचना के अधिकार (आरटीआई) से दूर क्यों रखा गया? ऐसे धार्मिक ट्रस्ट उसके तहत आते है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही 113 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और रोजाना के काम में भी सैकड़ों रुपए खर्च होते है, इन सबका हिसाब कौन देगा? देश में रह रहे 100 करोड़ वे ज्यादा हिन्दुओं में से अब तक लगभग 30 करोड़ लोगों ने ही दर्शन किए है, तो बाकि लोग क्या राम को नहीं मानते है। जब से यह घोटाला हुआ है, तब से राम मंदिर आने वाले लोगों की संख्या घटी है और चढ़ावा भी काफी कम हो गया है। विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री योगी पर भी उंगली उठा रहे है, जबकि मंदिर में होने वाले कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी हर माह रामलला के दर्शन करने अध्योध्या जाते है और वहां हो रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने की गति को भी देखते है, लेकिन वहां के सारे कामकाज की जिम्मेदारी ट्रस्ट की रहती है। इस प्रकरण में भाजपा के लिए चुनौती पैदा कर दी है क्योंकि उत्तरप्रदेश में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और विपक्ष चढ़ावे की चोरी और पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। भाजपा के लिए यही उचित होगा कि चढ़ावे चोरी की घटना की जांच में कोई भी ऐसी कड़ी न छोड़े जिससे कोर्ट में अपराधियों के निकलने की कोई गुंजाइश बने। जितनी जल्दी इन अपराधियों को सजा होगी, उतनी ही जल्दी हिन्दुओं का रोष कम होगा।

'सिर्फ स्कोर गिन रहे और सीखना भूल रहे हैं!'

डॉ. दीप्ति यादव

हर वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एक ही प्रश्न पूरे समाज में गूंजने लगता है—

'और कितने प्रतिशत आए?' यही प्रश्न मानो किसी विद्यार्थी की क्षमता, भविष्य और व्यक्तित्व का अंतिम निर्णय बन जाता है। लेकिन इस शोर के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं खो जाता है— 'उस बच्चे ने वास्तव में क्या सीखा?'

यही है शिक्षा और परीक्षा के बीच का अंतर, जिसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।

शिक्षा का उद्देश्य कभी भी अंक अर्जित करना नहीं था। उसका उद्देश्य है जिज्ञासा जगाना, सोचने की क्षमता विकसित करना, सही-गलत का विवेक देना और ऐसे नागरिक तैयार करना जो समस्या का बेहतर ढंग से समाधान कर सकें। दुर्भाग्य से आज शिक्षा का बड़ा हिस्सा अंकों की प्रतिस्पर्धा में सिमटता जा रहा है। विद्यार्थी विषय को समझने से अधिक उसे परीक्षा में लिखने योग्य बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं, और उससे भी अधिक शिक्षक तथा अभिभावक रचनात्मक सीखने पर अनजाने में केवल एक रणनीति बना चुके हैं।

यह कहना गलत होगा कि स्कोर महत्वहीन हैं। स्कोर आवश्यक हैं, क्योंकि वे किसी स्तर तक उपलब्धि का संकेत देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब हम स्कोर को ही सीखने का पर्याय मान लेते हैं। एक रिपोर्ट किसी विद्यार्थी की स्थिति बता सकती है, पर उसकी रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, संवेदनशीलता या जीवन की चुनौतियों से जूझने की योग्यता को कैसे माप सकती है?

आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान जैसे तीव्र परिवर्तन का समय है। जानकारी अब पुस्तकों तक सीमित नहीं है; वह हर मोबाइल फ़ोन में कुछ ही सेकंड में उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि यह सिखाना होना चाहिए कि जानकारी का सही उपयोग कैसे किया जाए, सही निर्णय कैसे लिए जाएँ और नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए।

यदि बच्चों से केवल यह उम्मीद की जाए

यह कहना गलत होगा कि स्कोर महत्वहीन हैं। स्कोर आवश्यक हैं, क्योंकि वे किसी स्तर तक उपलब्धि का संकेत देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब हम स्कोर को ही सीखने का पर्याय मान लेते हैं। एक रिपोर्ट किसी विद्यार्थी की स्थिति बता सकती है, पर उसकी रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, संवेदनशीलता या जीवन की चुनौतियों से जूझने की योग्यता को कैसे माप सकती है?

कि वे जितना पढ़ें, उतना ही लिखें, तो हम सीखने की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित कर देंगे। जबकि शिक्षा तब होती है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न पर विचार करता है, प्रयोग करता है, असफल होता है, फिर सीखता है और अपने अनुभवों से नए अर्थ गढ़ता है। सीखना एक जीवंत प्रक्रिया है, जबकि परीक्षा उसका केवल एक क्षणिक चित्र है।

इसी संदर्भ में लर्निंग एनालिटिक्स और डेटा विज्ञान शिक्षा के लिए नई संभावनाएँ लेकर आए हैं। यदि इनका उपयोग केवल मूल्यांकन के लिए न किया जाए, तो ये शिक्षक यह समझ सकते हैं कि कौन-सा विद्यार्थी किस अवधारणा में कठिनाई महसूस कर रहा है, किसे अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है और किस प्रकार की शिक्षण-प्रक्रिया उसके लिए अधिक प्रभावी होगी। डेटा का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंक देना नहीं, बल्कि उनके सीखने की यात्रा को समझना होना चाहिए। लेकिन तकनीक भी तभी सार्थक है, जब उसके केंद्र में मनुष्य हो। शिक्षा केवल एल्गोरिदम से नहीं चलती; वह शिक्षक की संवेदना, विद्यार्थी की जिज्ञासा और सीखने के वातावरण से निर्मित होती है। यदि इसे केवल आँकड़ों तक सीमित कर दिया जाए, तो वह केवल आँकड़ा बनकर रह जाएगी।

इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को भी यह याद रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा एक व्यक्ति है और बताइए, कितने अंक आए? का प्रश्न ही उसकी पहचान नहीं हो सकता। यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था रिपोर्ट कार्ड की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम ऐसे नागरिक तैयार करेंगे जो परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई अनुभव करेंगे। क्या यह समय नहीं आ गया है कि हम अपने बच्चों से यह पूछें— 'तुमने कितना सीखा?' न कि केवल 'तुम्हें कितने अंक मिले?'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समग्र विकास, कौशल-आधारित शिक्षा और अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है। अब चुनौती नीति बनाने की नहीं, बल्कि उसे अपने विद्यालयों और कक्षाओं में प्रभावी रूप से लागू करने की है। यदि सफलता को केवल प्रतिशत में मापा जाएगा, तो सच्चा सीखना उसी अनुपात में पीछे छूटता जाएगा।

समय आ गया है कि हम शिक्षा की सफलता को अंकों से नहीं, सीखने की गहराई से मापें। क्योंकि अंक यह बता सकते हैं कि विद्यार्थी ने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया, लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि उसने जीवन के लिए कितना सीखा।

शायद अब हमें अपने बच्चों से यह पूछना शुरू करना चाहिए— 'तुमने कितना सीखा?' न कि केवल 'तुम्हें कितने अंक मिले?' क्योंकि अंततः शिक्षा का उद्देश्य अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि अच्छे विचार, बेहतर निर्णय और अच्छा मनुष्य बनाना है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

स्कूलों में अब 20 मिनट की क्लास : बच्चों को दी जाएगी यौन शिक्षा और सुरक्षा की जानकारी

देश में बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को शामिल किया जाएगा। इसके तहत हर सप्ताह 20 मिनट की विशेष कक्षा लगाई जाएगी, जिसमें बच्चों को शरीर में होने वाले बदलाव, सुरक्षित व्यवहार और सही-गलत की पहचान के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को यौन शोषण, गुड टच-बैड टच और साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाए। कोर्ट का मानना है कि जब तक बच्चों को सही जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक उनके साथ होने वाले अपराधों को रोकना मुश्किल होगा।

यह कक्षा सप्ताह में एक बार आयोजित होगी। इसमें उम्र के अनुसार बच्चों को जानकारी दी जाएगी। छोटे बच्चों को शरीर के अंगों के सही नाम, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान तथा किसी के गलत व्यवहार करने पर किससे मदद मांगनी है, यह बताया जाएगा। बड़े बच्चों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव, आपसी सम्मान, रिश्तों की मर्यादा, साइबर बुलिंग और यौन शोषण से बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। पाठ्यक्रम में यह भी शामिल होगा कि यदि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वह चुप न रहे और अपने माता-पिता, शिक्षक या हेल्पलाइन से मदद ले।

केंद्र सरकार का कहना है कि आज के समय में बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण बहुत जल्दी विभिन्न जानकारियों तक

पहुंच जाते हैं। यदि उन्हें सही और वैज्ञानिक जानकारी स्कूल में नहीं मिलेगी तो वे गलत स्रोतों से भ्रमित हो सकते हैं। यौन शिक्षा का अर्थ अश्लीलता नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें शोषण से बचाना है। पॉक्सो एक्ट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद इसकी आवश्यकता और अधिक महसूस की गई है। कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों को यह तक पता नहीं होता कि उनके साथ जो हुआ, वह गलत था।

कई अभिभावक इस फैसले को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि कम उम्र में ऐसी जानकारी देने से बच्चे भटक सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जानकारी उम्र के अनुसार और वैज्ञानिक तरीके से दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं होगी, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित बनाना होगा। शिक्षकों को भी इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे इस विषय को संवेदनशीलता के साथ पढ़ा सकें। स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति और अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले हर वर्ष बढ़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश मामले परिचित लोगों द्वारा किए जाते हैं। यदि बच्चा शुरू से ही सही और गलत की पहचान करना सीख जाएगा, तो वह अपने बचाव के लिए आवाज उठा सकेगा। यह कक्षा बच्चों में आपसी सम्मान और समानता की भावना भी विकसित करेगी। लड़के और लड़कियों, दोनों को यह समझाया जाएगा कि किसी का भी शरीर उसका निजी अधिकार है और उसका सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है।

स्कूलों में 20 मिनट की यह कक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जानकारी से डर कम होता है और जागरूकता से अपराधों की रोकथाम संभव होती है। सरकार, अभिभावक और शिक्षक यदि मिलकर इस पहल को सफल बनाएं, तो हर बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा और बिना डर के खुलकर जीवन जी सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

18 करोड़ का तमाशा: 90 डिग्री का पुल और शून्य जवाबदेही

पूरे विश्व में मजाक बन चुका यह ओवरब्रिज आज सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। 18 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, पर नतीजा निकला एक ऐसा पुल, जिस पर न गाड़ी सुरक्षित चल सकती है और न ही उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। राज्य सरकार सो रही है, रेलवे चुप है और दोनों मिलकर सिर्फ एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शहर के बीचों-बीच बना यह पुल तकनीकी रूप से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। कारण है इसका 90 डिग्री का मोड़। सीधी सड़क पर चलती गाड़ी अचानक 90 डिग्री घूमेगी। मतलब पुल बना ही इस तरह है कि उसका उपयोग व्यावहारिक नहीं रह गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत में इंजीनियरिंग इसी स्तर की है, पर यहां के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। न शर्म आई, न जवाबदेही तय हुई।

सरकारी कागजों के अनुसार इस पुल पर 18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 18 करोड़ का मतलब समझते हैं? सैकड़ों स्कूल बन सकते थे, सैकड़ों अस्पताल बन सकते थे, हजारों गरीबों को रोजगार मिल सकता था। पर पैसा गया एक ऐसे प्रोजेक्ट में, जो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। पुल बनकर तैयार है, पर ताला लगा है क्योंकि डिजाइन में ही गड़बड़ी है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि डिजाइन पास करते समय गलती हो गई, नक्शा ठीक से नहीं देखा गया और तकनीकी जांच नहीं हुई।

18 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना जांच के कैसे पास हुआ? किसने हस्ताक्षर किए? किसने मंजूरी दी? उस इंजीनियर पर क्या कार्रवाई हुई? उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई? जवाब है—कुछ नहीं। सब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और जनता का पैसा डूब गया।

जैसे ही पुल की खामी सामने आई, दोनों विभाग आमने-सामने आ गए। राज्य सरकार कहती है कि यह रेलवे का प्रोजेक्ट था। रेलवे कहता है कि नक्शा राज्य सरकार ने पास किया था। मीटिंग होती है, फोटो खिंचती है और फाइल बंद हो जाती है। इधर जनता 18 करोड़ के नुकसान का बोझ ढो रही है। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने माफी नहीं मांगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि सुधार किया जाएगा।

सरकारी कागजों के अनुसार इस पुल पर 18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 18 करोड़ का मतलब समझते हैं? सैकड़ों स्कूल बन सकते थे, सैकड़ों अस्पताल बन सकते थे, हजारों गरीबों को रोजगार मिल सकता था। पर पैसा गया एक ऐसे प्रोजेक्ट में, जो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। पुल बनकर तैयार है, पर ताला लगा है क्योंकि डिजाइन में ही गड़बड़ी है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि डिजाइन पास करते समय गलती हो गई, नक्शा ठीक से नहीं देखा गया और तकनीकी जांच नहीं हुई। 18 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना जांच के कैसे पास हुआ? किसने हस्ताक्षर किए? किसने मंजूरी दी? उस इंजीनियर पर क्या कार्रवाई हुई? उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई? जवाब है—कुछ नहीं।

अब नया फरमान आया है कि पुल के पास 2.5 मीटर अतिरिक्त जगह लेकर मोड़ को चौड़ा किया जाएगा। मतलब फिर से टेंडर, फिर से पैसा, फिर से कमीशन। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच ठेकेदार से लेकर बाबू तक सब मालामाल। कौन पूछेगा कि पहली बार गलती क्यों हुई? कौन पूछेगा कि दूसरी बार गलती न हो, इसकी गारंटी क्या है?

इस पुल का मकसद था जाम से राहत दिलाना, पर आज जाम वैसे ही है। उल्टा 18 करोड़ का बोझ जनता के सिर पर और चढ़ गया। अगर यह पैसा सड़कों पर लगता तो दर्जनों सड़कें बन जातीं। अगर यह पैसा शिक्षा पर लगता तो हजारों बच्चों का भविष्य बन जाता। पर नहीं, पैसा गया एक ऐसे पुल में, जो धरोहर बनकर रह गया है—देखने की धरोहर, हंसने की धरोहर और शर्म करने की धरोहर।

किसी भी प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र से पूछ लीजिए, वह बता देगा कि ओवरब्रिज पर 90 डिग्री का मोड़ नहीं दिया जाता। वाहन की गति, मोड़ का रेडियस और सड़क की चौड़ाई जैसी सभी बातों की गणना की जाती है। यहां तो सब नियम ताक पर रख दिए गए और नतीजा सामने है। अब कहा जा रहा है कि तकनीकी समिति बनाई जाएगी, रिपोर्ट आएगी और जांच होगी। पर तब तक अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और जनता भूल जाएगी।

सबसे खतरनाक बात यह है कि सिस्टम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीडिया में खबर चली, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, विदेशों तक में चर्चा हुई, लेकिन न कोई जांच, न कोई निलंबन, न कोई एफआईआर। क्योंकि यहां गलती करने वाले सुरक्षित हैं और सवाल पूछने वाले परेशान।

भारत चांद पर पहुंच रहा है। भारत डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। भारत विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है और उसी भारत में 18 करोड़ का पुल 90 डिग्री का मोड़ लेकर खड़ा है। विदेशी लोग पूछते हैं कि क्या आपके यहां इंजीनियर ऐसे ही होते हैं? क्या आपके यहां टैक्स का पैसा ऐसे ही उड़ाया जाता है? इसका जवाब किसके पास है?

अब और बहाने नहीं चलेंगे। अब और समितियां नहीं बनेंगी। तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई हो। पुल को या तो तुरंत सुधारकर चालू किया जाए या तोड़कर नया बनाया जाए। 18 करोड़ रुपये की वसूली दोषियों से की जाए। भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।

आम आदमी पूछ रहा है कि मेरा टैक्स कहां गया? आम आदमी पूछ रहा है कि मेरे पैसे से बना पुल क्यों नहीं चल रहा? आम आदमी पूछ रहा है कि गलती करने वाले आज भी कुर्सी पर क्यों हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का विकास?

यह पुल एक पुल नहीं है, यह हमारे सिस्टम की लाश है। यह बताता है कि कैसे बिना योजना के काम होते हैं, कैसे बिना जवाबदेही के पैसा बर्बाद किया जाता है और कैसे गलती के बाद भी कोई शर्मिंदा नहीं होता। 18 करोड़ रुपये खर्च करके हमने एक तमाशा खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर दुनिया हंसती है और हम चुप रहते हैं। अब और चुप नहीं रहा जाएगा। अब हिसाब देना होगा, क्योंकि जनता का पैसा जनता की अमानत है और अमानत में खयानत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। वरना कल फिर कोई 90 डिग्री का पुल बनेगा, फिर 18 करोड़ रुपये डूब जाएंगे और फिर हम ऐसे ही बैठकर अफसोस करेंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)